



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252944
CG-DL-E-14032024-252944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1200]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 1200]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1262(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), जमीनी स्तर पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम का संचालन कर रहा है और यह पुनर्वास वृत्तिकों के प्रशिक्षण और पुनर्वास जागरूकता सृजन हेतु जिला स्तर में अवसंरचना और क्षमता निर्माण को सुकर बनाता है जिसे जिला प्रबंधन टीम (डीएमटी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

और इस स्कीम के अधीन, वर्तमान स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यष्टिक फायदाग्राहियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं और पुनर्वास पर जागरूकता सृजन और पुनर्वास वृत्तिकों को प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) की सेवाएं दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को प्रदान की जाती हैं;

और स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु बालक को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अध्यधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बालक किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन (अपडेट)) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में स्थित कोई आधार नामांकन अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी आई ए) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु यह कि जब तक बालक को आधार नियत नहीं हो जाता तब तक निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अध्यधीन होने के रहते हुए, इस स्कीम के अधीन ऐसे बालक को प्रसुविधा दी जाएगी, अर्थात्-

- (क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के पश्चात् (बायोमेट्रिक्स संग्रह के साथ) नामांकित किया गया था तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मीट्रिक अपडेट पहचान पर्ची, या;
- (ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और
- (ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-
 - (i) जन्म-प्रमाणपत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; या
 - (ii) विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा स्म्यक्तः हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें अभिभावक के नाम अंतर्विष्ट हैं; और
- (ग) वर्तमान स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-
 - (i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; या
 - (ii) राशन कार्ड; या
 - (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; या
 - (iv) पेंशन कार्ड; या
 - (v) सेना कैटीन कार्ड; या
 - (vi) कोई भी सरकारी कुटुंब पात्रता कार्ड; या
 - (vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि, उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को उक्त आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा।
3. जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अंगीकृत किए जाएंगे, अर्थात् –
- (क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन सुविधा को अंगीकृत किया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से प्रसुविधा के परिदान के लिए फिंगर-प्रिंट अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा;
 - (ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की दशा में, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, यथास्थिति किए जाएंगे;
 - (ग) जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं होने की दशा में, स्कीम के अधीन प्रसुविधा वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अब स्थानों पर प्रदान की जाएगी।
4. उपर्युक्त में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बालक इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं होगा, यदि अधिप्रमाणन के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के सबूत को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करते हुए उसे प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रसुविधा दी जाती है, वहां उसके अनुरक्षण के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और संपरीक्षा आवधिक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से की जाएगी।
5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1262(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department) in the Government of India is administering a Central Sector Scheme namely District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) (hereinafter referred to as the Scheme) to provide comprehensive rehabilitation services at the grass root level and also it facilitates creation of infrastructure and capacity building at the district level for awareness generation on rehabilitation and training of rehabilitation professionals, which is being implemented through District Management Team (DMTs) (hereinafter referred to as the implementing agencies).

And whereas, under the scheme, comprehensive rehabilitation services are provided to the individual beneficiaries and the services of awareness generation on rehabilitation and the training of rehabilitation professionals

(hereinafter referred to as benefits) is given to the persons with disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry or Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely:-

- (a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;
- (ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and
- (b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-
 - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
 - (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and
- (c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:-
 - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
 - (ii) Ration Card; or
 - (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or
 - (iv) Pension Card; or
 - (v) Army Canteen Card; or
 - (vi) any Government Family Entitlement Card; or
 - (vii) any other document as specified by the Ministry or Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry or Department through its Implementing Agency.
4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through its Implementing Agency.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.